

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 07 अक्टूबर 2026 वर्ष-9, अंक-246 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com



www.facebook.com/krantisamay1



www.twitter.com/krantisamay1

मप्र में दो बार आयोजित की जाएगी एमपीपीएससी की परीक्षा, मुख्यमंत्री डॉ.मोहन की बड़ी घोषणा

भोपाल (एजेंसी)। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 06 अक्टूबर को भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026 में युवाओं से संवाद कर रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव में प्रदेश के 20 हजार से अधिक युवा शामिल हुए। कॉन्क्लेव में युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता, नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े अवसरों की जानकारी दी गई और सीएम मोहन ने सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम मोहन ने प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। सीएम मोहन ने युवाओं को बड़ी सीमाएं देते हुए ऐलान किया कि अगले वर्ष से मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी की परीक्षा दो बार आयोजित की जाएगी।



सीएम यूथ कॉन्क्लेव-2026 की बड़ी घोषणाएं

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग वलासेस शुरू होंगी। उच्च शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देने के लिए शोधार्थियों मिलने वाली राशि 16 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रूपए प्रतिमाह की जाएगी। सभी शासकीय महाविद्यालयों में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस कम्यूटिंग लेब की स्थापना की जाएगी। स्टार्टअप के लिए अच्छे आइडियाज मिलें, इसके लिए 5 करोड़ रूपए का आइडिया फंड बनाने का प्रावधान किया गया है। स्नातकोत्तर की छात्राओं को गांव की बेंटी और प्रतिभा किरण योजना के

दायरे में शामिल किया जाएगा। युवाओं के प्लेसमेंट कराने के लिए एक एजेंसी नियुक्त की जाएगी। सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए काम करेगी। राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की 500 नई ईकाइयां बनाई जाएंगी। शोध संस्था में 1 करोड़ रूपए का फंड विश्वविद्यालय निधि से स्थापित किया जाएगा। प्रदेश के एक लाख युवाओं को कौशल उन्नयन योजना से जोड़ा जाएगा। प्रत्येक संभाग में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2027 में फिर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) का आयोजन होगा।

2026 का फिजिक्स नोबेल फ्रांसिस हाल्जेन को मिला

अंतरिक्ष से आने वाले रहस्यमयी कणों को पकड़ने का तरीका खोजा

स्टॉकहोम (एजेंसी)। बेलजियम में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रांसिस हैलजेन को 2026 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्हें यह पुरस्कार अंतरिक्ष से धरती तक आने वाले बेहद ताकतवर न्यूट्रिनो को पकड़ने और उनके बारे में पता लगाने में अहम काम के लिए दिया गया है। उन्होंने दक्षिणी ध्रुव की बर्फ में न्यूट्रिनो पकड़ने वाली आइसक्यूब ऑब्जर्वेटरी बनाने का विचार दिया था। नोबेल पुरस्कार के विजेताओं को दिसंबर में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मेडल, डिप्लोमा और पुरस्कार राशि दी जाएगी। 2026 में नोबेल पुरस्कार की राशि करीब 11.5 करोड़ रूपए है। आइसक्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी दक्षिणी ध्रुव में है। इसके



फ्रांसिस हैलजेन

सेंसर दक्षिणी ध्रुव की करीब 1.5 से 2.5 किलोमीटर गहरी बर्फ के अंदर लगाए गए हैं। अंतरिक्ष के न्यूट्रिनो पकड़ने के लिए बर्फ का इस्तेमाल- न्यूट्रिनो बहुत छोटे कण हैं, जो सूजन, तारों और अंतरिक्ष की बेहद ताकतवर घटनाओं से निकलते हैं। अरबों न्यूट्रिनो हर सेकंड हमारे शरीर और धरती के आर-पार निकल जाते हैं, लेकिन हमें उनका पता तक नहीं चलता इन कणों की खास बात यह है कि वे अंतरिक्ष से निकलकर लगभग सीधी दिशा में धरती तक पहुंचते हैं और रास्ते में बहुत कम बदलते हैं। इसलिए अगर वैज्ञानिक इन्हें पकड़ लें, तो वे पता लगा सकते हैं कि ये ब्रह्मांड में कहाँ और किस घटना से निकले थे। लेकिन न्यूट्रिनो को पकड़ना आसान नहीं है।

संक्षिप्त

समाचार

बीसीसीआई मीटिंग के बाद हरमनप्रीत ने छोड़ी कप्तानी

उनकी अगुआई में भारत ने पहली बार महिला वर्ल्ड कप जीता, स्मृति बन सकती है अगली कप्तान

नई दिल्ली (एजेंसी)। हरमनप्रीत कोर ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। उन्होंने मंगलवार को इस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी। यह फैसला एक दिन पहले गुवाहाटी में हुई



बीसीसीआई की मीटिंग के बाद आया है। बैठक में हरमनप्रीत, उपकप्तान स्मृति मंधाना और कोच अमोल मजुमदार शामिल हुए थे। टीम के भविष्य और कप्तानी को लेकर भी चर्चा हुई। हरमनप्रीत के बाद स्मृति मंधाना को अगला कप्तान बनाया जा सकता है। 37 साल की हरमनप्रीत के नाम कई रिकॉर्ड हैं। इनमें बतौर कप्तान भारत को पहला महिला वर्ल्ड कप जिताना शामिल है। उनकी कप्तानी में टीम ने 2012, 2016, 2022 और 2026 एशिया कप का खिताब भी अपने नाम किया। 2012 एशिया कप में हरमनप्रीत ने सिर्फ फाइनल में कप्तानी की थी। बाकी मैचों में मिताली राज ने टीम की कप्तान संभाली थी।

बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी की 6 सीटों पर वोटिंग

बंगाल में पुलिस ने हुमायूँ कबीर को गिरफ्तार किया, ममता न सीएम-विधायक, न उम्मीदवार

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के चार राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में 6 सीटों पर मंगलवार को वोटिंग हुई। इस दौरान आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी)



के प्रमुख और विधायक हुमायूँ कबीर को बंगाल के मुर्शिदाबाद में उनके पार्टी कार्यालय से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उन पर चुनाव में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। उनके बेटे गुलाम नबी आजाद भी रेजीनगर से उम्मीदवार हैं। वहीं, मीडिया से बात करते हुए नंदीग्राम से कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान ने आरोप लगाया है कि उनके पोलिंग एजेंट्स को जबरन उठाया जा रहा है।

27 के लिए 6.6 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत किया, पहली तिमाही के मजबूत आंकड़ों का फायदा मिला

वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.1 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले अप्रैल में वर्ल्ड बैंक ने एफबाय 27 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.6 प्रतिशत बताया था। मंगलवार, 6 सितंबर को जारी लेटेस्ट रिपोर्ट 'इंडिया डेवलपमेंट अपडेट' में वर्ल्ड बैंक ने यह बात कही है।

ग्लोबल ट्रेड और दुनिया में तनाव के बावजूद भारत की इकोनॉमी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8 प्रतिशत रही थी।



गांव-शहरों में मांग बड़ी, एक्सपोर्ट भी बढ़ा- वर्ल्ड बैंक के अनुसार, भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में निवेश और घरेलू खपत यानी प्राइवेट कंजम्पशन का सबसे बड़ा योगदान रहा है।

गांव और शहर दोनों में मांग- अच्छी खेती, सरकारी से किसानों को सिंधी सहायता और सब्सिडी के चलते डिमांड बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर टैक्स में राहत और जीएसटी कटौती के बाद शहरी खपत में भी उछाल देखने को मिला है।

स्कूलों में रोजाना संविधानकी प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य करने की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिलेबस में पहले से ही शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर एक ऐसी राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग की गई थी जिसके तहत स्कूलों में सुबह की असेंबली के दौरान छात्रों को संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को इस पीआईएल पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ,



संदीप मेहता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि प्रस्तावना पहले से ही स्कूल के पाठ्यक्रम का हिस्सा है और इसे छटी कक्षा से ही छात्रों को पढ़ाया जाता है। संविधान की प्रस्तावना को राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग खारिज- दिल्ली यूनिवर्सिटी के राजधानी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। इस याचिका में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और CBSE के स्कूली बच्चों में संवैधानिक जागरूकता को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।



नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने विपक्षी सांसदों के संसद से चुनाव आयोग तक मार्च को बीच में ही रोके जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग हमसे क्यों नहीं मिल रहे है? पुलिस हमें चुनाव आयोग जाने से क्यों रोक रही है

विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सांसदों के मार्च को पुलिस ने रोका

ज्ञानेश कुमार से मिलने पर अड़े राहुल गांधी, आकाशवाणी भवन में धरना वयों नहीं मिल रहे

राहुल गांधी बोले- 300 सांसदों को रोका गया, पुलिस हमें धमका रही

और धमका रही है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद से हमारे साथ 300 सांसद चुनाव आयोग जाना चाहते थे। हालांकि, उन्हें बीच में ही रोक दिया गया। हम करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आखिर 300 सांसदों को क्यों रोका गया है। देश में क्या हो रहा- लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि करीब 300 सांसद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो अन्य चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमें यहीं रोक



दिया। हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें यहां क्यों रोका गया है। हमें समझ नहीं आ रहा कि समस्या क्या है,

इंडिया गठबंधन के विरोध मार्च में पहली बार दिल्ली बीजेपी की 'न्यूट्रल सहयोगी'

नई दिल्ली (एजेंसी)। निर्वाचन आयोग के खिलाफ विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के सांसदों के सांसदों ने मंगलवार को विरोध मार्च निकाला। जिसमें पहली बार बीजेपी की 'न्यूट्रल सहयोगी' मानी जाने वाली बीजेडी ने भी शिरकत की। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया। बीजेपी नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स पोस्ट में बीजेडी सांसदों के मार्च में शामिल होने की जानकारी दी। संसद के मकर द्वार से निकला विपक्ष का मार्च नीति आयोग के पास ही रुक गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी।



बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, राहुल गांधी से पूछे 10 सवाल

‘हमारी मदद ज्ञानेश कुमार नहीं, गणेश जी कर रहे’

नई दिल्ली (एजेंसी)। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजित पात्रा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि कुछ विपक्षी पार्टियां खासकर कांग्रेस पार्टी देश में सरकार बदलने और किसी तरह राहुल गांधी को सत्ता में बिठाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए भारतीय लोकतंत्र और देश की संवैधानिक संस्थाओं पर एक साथ हमला किया जा रहा है। यह प्रक्रिया कुछ महीने पहले शुरू नहीं हुई है बल्कि यह कई सालों से चल रही है। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी ने बार-बार किसी भी तरह से राहुल गांधी को लॉन्च और रिलॉन्च करने की कोशिश की है। संजित बोले- हमारी मदद गणेश जी कर रहे- संजित पात्रा ने आगे कहा कि हमारी मदद ज्ञानेश कुमार नहीं कर रहे हैं, हमारी मदद गणेश जी कर रहे हैं।



बुद्धि, विद्या, ज्ञान और विवेक के देवता गणेश जी हैं। देश की जनता के पास बुद्धि, विवेक, ज्ञान है और जनता जानती है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले लोगों को वोट नहीं देना है। वोट उसको देना है जिसने कहा है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा। एसआईआर पर फैलाई जा रही

फेक न्यूज- बीजेपी नेता ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से एसआईआर को लेकर गलतफहमीयां और फेक न्यूज फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। उस याचिका में मुख्य मांग थी कि चीफ इलेक्शन कमिशनर को हटा दिया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए।

राहुल गांधी के झूठ का पुलिंदा खोलूंगा: पात्रा

संजित पात्रा ने कहा कि आज, मैं एक-एक करके राहुल गांधी के झूठ का पुलिंदा खोलूंगा। इस पूरे एक्स पोस्ट में, राहुल गांधी ने चार गुमराह करने वाले शब्दों इस्तेमाल किए हैं। पहला, 'फॉर्म 6 को गैरकानूनी तरीके से बदला गया है।' दूसरा, 'फॉर्म 6 को एकतरफा बदला गया।' तीसरा, 'इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी की मदद करने की कोशिश कर रहा है।' और चौथा, 'इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भारतीय लोकतंत्र पर क्रिमिनल हमला।'।

गुजरात में भीषण सड़क हादसा

तेज रफ्तार एसयूवी ट्रेलर ट्रक से टकराई, सात लोगों की दर्दनाक मौत

भावनगर (गुजरात) (एजेंसी)। गुजरात के भावनगर जिले में मंगलवार को उस समय चीखपुकार मच गई जब हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस घटना में सात लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात के भावनगर जिले में एक हाईवे पर खड़ी ट्रेलर ट्रक से एसयूवी के टकराने से सात लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधीक्षक नितेश पांडे ने बताया कि पीड़ित भावनगर से अलग जा रहे थे, जहाँ वे एक शिपयार्ड में काम करते थे। पुलिस के अनुसार, यह हादसा सुबह करीब 10 बजे जिले के तलाजा तालुका में ट्रापाज गाँव के पास भावनगर-सोमनाथ नेशनल हाईवे के किनारे सर्विस रोड पर हुआ, जब तेज रफ्तार एसयूवी खड़ी ट्रेलर से टकरा गई।



नरेन्द्र मोदी ने रचा 25 वर्षों के स्वर्णिम सुशासन का कीर्तिमान

(लेखक- सुरेश पत्तौरी)

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 7 अक्टूबर 2026 को अपनी अनवरत राष्ट्रसेवा के कीर्तिमान गढ़ने जा रहे हैं। यह वह ऐतिहासिक दिन होगा, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री और तत्पश्चात देश के प्रधानमंत्री के रूप में 7 अक्टूबर 2026 को अपनी राष्ट्रसेवा के 25 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। यह भारत के राजनैतिक परिदृश्य य में नया रिकार्ड होगा। उन्होंने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में तथा 26 मई 2014 को देश के प्रधानमंत्री के रूप में दायित्व संभाला था।

मोदी के दौर में गुजरात की विकास यात्रा श्री नरेन्द्र मोदी के मुख यमंत्री रहते हुए गुजरात में अभूतपूर्व विकास हुआ। बुनियादी ढांचे, जल, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, उद्योग और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में सराहनीय कार्य हुए, जिसने एक आत्मविश्वासी, प्रगतिशील और आकांक्षी गुजरात की नींव रखी। 2003 में शुरू हुए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में निवेशकों, बड़े उद्यमियों और नीति निर्माताओं को एक साथ लाया गया, जिससे संयुक्त उपक्रमों, व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिला। गुजरात में प्रारंभ ज्योतिग्राम योजना ने 1,290 करोड़ रुपये के निवेश के माध्यम से 18,000 से अधिक गांवों में 24 घंटे तीन-फेज बिजली पहुंचाई। गुजरात 2003-04 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना लागू करने तथा 2006 में अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना। 2001 और 2014 के बीच गुजरात के विकास ने विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी परियोजनाओं के साथ जन-केंद्रित पहलों को जोड़ा और दीर्घकालिक विकास की नींव रखी। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में गुजरात में विकास की ऐसी ठोस बुनियाद रखी गई, जिसे कालांतर में गुजरात माडल के रूप में जाना गया।

संकल्प से सिद्धि तक - श्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रसेवा यात्रा श्री नरेन्द्र मोदी ऐसे तपे-तपाए जननेता हैं, जिनमें कुंदन की कठोरता भी है और चंदन की शीतलता भी विद्यमान है। उनके चिंतन में राष्ट्र, राष्ट्रद्रष्टा एवं राष्ट्रद्रष्टित सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने तमाम ऐसे फैसले लिए जो राष्ट्र के लिए

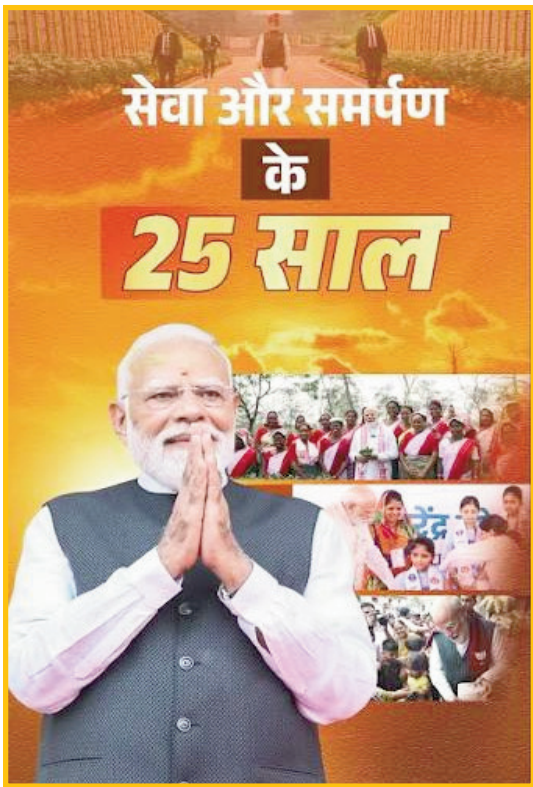
हितकारी थे। चाहे धारा 370 की समाप्ति हो, भय य श्री राम मंदिर का निर्माण हो या सीमाओं की अभेद्य सुरक्षा हो। चंद्रयान-3 व ख़िव स सम्मेलन की सफलता से लेकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत तक, उनके हर कदम ने भारत को सशक्त बनाया है। स्वच्छ भारत से जल जीवन मिशन तक, उच्च जलवा योजना से आयुष्मान भारत तक, किसान सम्मान निधि से लखपति दीदियों की आत्मनिर्भरता तक, हर योजना का एक ही ध्येय रहा है कि सबका जीवन बेहतर हो और भारत समर्थ बने। रक्षा के क्षेत्र में तो भारत पूर्णतः आत्मनिर्भर बन चुका है। श्री नरेन्द्र मोदी की जनसेवा के ये 25 वर्ष सिर्फ सत्ता के उपभोग के नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के विश्वास पर खरा उतरने, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने और भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल पर नजर डालें तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं में नवाचार और आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और डिजिटल रिकल इंडिया जैसी योजनाओं का सूरपात हुआ। आज भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हमारी जीडीपी वृद्धि दर भी 7.8व है। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के करोड़ों परिवारों को पक्के घर दिए गये। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लाखों शौचालयों का, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कराया गया। उच्चजलवा योजना के माध्यम से गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान कर उनके स्वास्थ्य य और गरिमा की रक्षा की गई। बेहतर स्वास्थ्य य सुविधा के मद्देनजर आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई, जिससे 60 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य य बीमा का सुरक्षा कवच मिला। जल जीवन मिशन से हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है। सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों, हवाई अड्डों और डिजिटलीकरण में उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिल रही है। ग्रामीण भारत में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में मेट्रो और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं मूर्तरूप ले रही हैं।

मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का सिद्धांत है- रिकार्ड, परफार्म एवं ट्रांसफॉर्म। इस सरकार ने गरीबों के सम्मान, युवाओं के सामर्थ्य, किसानों की समृद्धि व महिलाओं के सशक्तिकरण को राष्ट्र निर्माण का विशेष आधार बनाया। मोदी जी ने किसानों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए अनेक योजनाओं का प्रावधान किया। महिला सशक्तिकरण मोदी के विकास एजेंडे का प्रमुख हिस्सा है। तीन तलाक कानून की समाप्ति से मुस्लिम महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। मातृवंदन योजना, नारी शक्ति वंदन और 33 प्रतिशत आरक्षण से महिलाओं के जीवन में नई उम्मीद जगी है। केंद्र सरकार का लक्ष्य तीन करोड़ लखपति दीदी बनाने का है, जिनमें से डेढ़ करोड़ से अधिक लखपति दीदी अपना गरिमायम जीवन जी रही हैं। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों का आत्मसम्मान बढ़ा है।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सुशासन, गरीब कल्याण और राष्ट्र प्रथम का संकल्प आज उनकी समावेशी राजनीति की पहचान बन चुका है। उनकी जनकल्याणकारी योजनाओं से भारत समरस विकास के नये सोपान नापते हुए सतत गतिमान है। मोदी जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबी यह है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति पर उनकी नजर सबसे पहले पहुंचती है। सर्वहारा वर्ग के दिल की बात की जाए तो जिसको किसी ने नहीं पूछा, उसे हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पूजा।

व्यक्ति व एवं कृतित्व व्यक्तियुद्ध का की पहचान मोदी जी के 25 वर्षों की इस अनवरत राष्ट्रसेवा के कालखण्ड में उनके व्यक्तित्व में तपस्वी, युगदृढ़ टा और जननायक के दर्शन होते हैं। उनकी अविराम राष्ट्रसेवा संकल्प से सिद्धि का प्रतिबिम्ब है। उन्होंने बीते 25 वर्षों के दौरान एक दिन भी अवकाश नहीं लिया। अपने बहुआयामी और विराट व्यक्तित्व से आज मोदी जी समूचे विश्व में शीर्ष नेता के रूप में जाने-पहचाने जाते हैं। मोदी जी को 36 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से विभूषित किया है। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व में विगत 25 वर्षों में वाइब्रेंट गुजरात से लेकर भारत को विश्व में वंच पर प्रतिष्ठे थापित किया है। श्री मोदी की जब हम 25 वर्षों की सुशासन यात्रा को



देखते हैं तो यह राष्ट्रपट होता है कि यह भारत के पुनरुत्थान की यात्रा है। मुख यमंत्री के रूप में उन्होंने सिखाया कि राज्य का विकास कैसे होता है और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने दिखाया कि देश कैसे विकसित होता है। देश के नव निर्माण के शिल्पकार दूरदर्शी श्री नरेन्द्र मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प लेकर भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने में अर्हनिश लगे हुए हैं। (लेखक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री हैं)

सफेद सोने का संकट और किसानों की जमीनी हकीकत

(लेखक-दिलीप कुमार पाठक)

(07 अक्टूबर विश्व कपास दिवस)

भारत के कृषि और औद्योगिक ढांचे में कपास केवल एक व्यापारिक फसल नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। देश के करीब 60 लाख किसान सीधे तौर पर इसकी खेती से जुड़े हैं, जबकि कपड़ा उद्योग के माध्यम से यह सेक्टर 4 से 5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। राष्ट्रपिता गांधी जी ने कहा था कि भारत का उद्धार उसके कताई चक्र और खादी में निहित है, जो देश के करोड़ों भूखे लोगों को आजीविका दे सकता है। गांधी जी का यह विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस के वैश्विक आयोजन के बीच, भारतीय कपास क्षेत्र के सरकारी आंकड़ों और खेतों के कड़वे सच के बीच के फासले का तटस्थ विश्लेषण बेहद जरूरी हो जाता है।

वैश्विक परिदृश्य में भारत कपास के बुवाई क्षेत्र के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। देश के लगभग 114.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है। उत्पादन की दृष्टि से भारत, चीन के बाद विश्व में दूसरे पायदान पर आता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, चालू सीजन में देश का कुल कपास उत्पादन लगभग 290.91 लाख गांठ दर्ज किया गया, जबकि हमारी घरेलू खपत का आंकड़ा 328 लाख गांठ के आसपास रहा। यह अंतर स्पष्ट करता है कि भारतीय कपड़ा मिलों और निर्यात की मांग को

पूरा करने के लिए घरेलू मोर्चे पर अभी लंबी दूरी तय करनी बाकी है। प्रति गांठ का वजन 170 किलोग्राम होता है।

आंकड़ों के पीछे जो सबसे बड़ा ढांचगत संकट है, वह है भारत की बेहद कम उत्पादकता। वैश्विक स्तर पर औसत प्रति हेक्टेयर उत्पादन जहां बहुत अधिक है, वहीं भारत में यह महज 431 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर अटका हुआ है। इसका मुख्य कारण यह है कि देश का लगभग 67 प्रतिशत कपास क्षेत्र आज भी पूरी तरह से अनिश्चित मानसून और वर्षा पर निर्भर है। केवल 33 प्रतिशत क्षेत्र को ही सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा प्राप्त है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में बेमौसम बारिश और लंबे सूखे के कारण हर साल लाखों हेक्टेयर फसल खेत में ही नष्ट हो जाती है।

दूसरा बड़ा संकट लागत और कीटों के प्रबंधन का है। बीटी कॉटन तकनीक की रोग प्रतिरोधक क्षमता अब धीरे-धीरे दम तोड़ रही है। पिछले कुछ सीजन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के ब्लैट में गुलाबी सूड़ी के भीषण प्रकोप ने किसानों को तबाह किया है। कीटों से फसल बचाने के चक्कर में महंगे कीटनाशकों और रासायनिक खादों का अंधाधुंध इस्तेमाल बढ़ा है, जिसने खेती की इनपुट कॉस्ट को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया है। लागत बढ़ने और उजड़ घटने के इस दोहरे चक्रव्यूह ने कपास उत्पादक किसानों को कर्ज के जाल में धकेल दिया है।



हालाँकि, संकट की गंभीरता को देखते हुए नीतिगत स्तर पर कुछ बड़े कदम उठाए गए हैं। विपणन सीजन के लिए सरकार ने कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि की है। मध्यम स्टेपल कपास का दाम बढ़ाकर 8,267 रुपये और लंबे स्टेपल का दाम 8,667 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 557 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार ने 5,659 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ कपास उत्पादकता मिशन को जमीन पर उतारा है। इस मिशन का दीर्घकालिक लक्ष्य वर्ष 2031 तक देश के उत्पादन को 498 लाख गांठ तक पहुंचाना है, जिसमें 14 राज्यों के 32 लाख किसानों को आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों से जोड़ने का खाका खींचा

गया है। विश्व कपास दिवस के इस मौड़ पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को पुनर्गठित करना होगा। केवल एमएसपी बढ़ाना या बुवाई का रकबा बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। हमें तत्काल रूप से उच्च घनत्व रोपण प्रणाली, जल संरक्षण के लिए ड्रिप इरिगेशन और जलवायु-अनुकूल बीजों के स्वदेशी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में सुधार नहीं होगा और कीटों के संकट का स्थायी वैज्ञानिक समाधान नहीं खोजा जाएगा, तब तक सफेद सोने की यह चमक देश के अन्नदाता के जीवन में उजाला नहीं ला पाएगी। (लेखक संभवकार हैं) (यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

कौन है नीतिनिष्ठ व्यक्ति?

सदाचार एक व्यापक और सार्वभौम तत्व है। देशकाल की सीमाएं इसे न तो विभक्त कर सकती हैं और न इसकी मौलिकता को नकार सकती हैं।

जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सबके लिए होता है, उसी प्रकार सदाचार के मूलभूत तत्व मानव में अभय, मृदुता, सत्य, सरलता, करुणा, धैर्य, कर्तव्यनिष्ठ और व्यक्तिगत संग्रह का संयम और प्रामाणिकता होती है, वह नीतिमान कहलाता है। जो व्यक्ति सत्य के प्रति समर्पित होता है, अन्याय का प्रतिकार करते समय भयभीत नहीं होता, अपनी भूल ज्ञात होने पर उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करता और कठिनतम परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है, वह अभय का साधक होता है।

कोमलता का नाम मृदुता है। यह सामूहिक जीवन की सफलता का सूत्र है। इसके द्वारा

भी स्थिति में नीति के अतिप्रमाण को अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता। नीतिनिष्ठ व्यक्ति को परिभाषित करते हुए कहा गया है- जिस व्यक्ति में अभय, मृदुता, सत्य, सरलता, करुणा, धैर्य, कर्तव्यनिष्ठ और व्यक्तिगत संग्रह का संयम और प्रामाणिकता होती है, वह नीतिमान कहलाता है। जो व्यक्ति सत्य के प्रति समर्पित होता है, अन्याय का प्रतिकार करते समय भयभीत नहीं होता, अपनी भूल ज्ञात होने पर उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करता और कठिनतम परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है, वह अभय का साधक होता है।

कोमलता का नाम मृदुता है। यह सामूहिक जीवन की सफलता का सूत्र है। इसके द्वारा

व्यक्ति के जीवन में सरसता आती है। मृदु स्वभाव में लोच होती है, इस स्वभाव वाला व्यक्ति किसी भी वातावरण को अपने अनुकूल बना लेता है। सत्य का अर्थ है यथार्थता। जो तथ्य जैसा है उसे वैसा ही जानना, मानना, स्वीकार करना और निभाना सत्य है। सत्य की साधना कठिन अवश्य है, पर है आत्मतोष देने वाली। आर्जव सरलता का पर्यायवाची शब्द है। सरलता सदाचार की आधारभूमि है। इसी उर्वरा में सदाचार की पौध फलती-फूलती है। मायावी व्यक्ति कभी सदाचारी नहीं हो सकता। करुणा सदाचार का मूल है। जिस व्यक्ति के अंतःकरण में करुणा नहीं होती, वह अहिंसा के सिद्धांत को समझ नहीं सकता। अहिंसा के बिना समता का विकास नहीं होता।



रूस की लैब में प्लेग के वायरस- सुरक्षा चूक या जैविक युद्ध की तैयारी?

(लेखक- सनत जैन)

रूस के साइबेरिया में इरकुत्स्क स्थित एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट की 28 वर्षीय, प्रयोगशाला कर्मचारी दार्या शिपिलोवा की मौत ने दुनिया का ध्यान एक बार फिर हाई-कंटेनमेंट लेबोरेटरीज और जैव-सुरक्षा की ओर खींचा है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है, काम के दौरान प्लेग बैक्टीरिया से भरी टेस्ट ट्यूब टूट गई थी। उसके बाद महिला गंभीर रूप से बीमार हुई। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके संपर्क में आए करीब 200 लोगों को निगरानी में रखे जाने की खबर सामने आई है। यहां सबसे जरूरी बात है, घटना को लेकर विरोधाभासी जानकारी मिल रही है। रूसी स्वास्थ्य निगरानी संस्था रोशपोटरेबनावर का कहना है, महिला की मौत का कारण अभी अज्ञात निर्मांनियामक के वायरस हैं। जांच में उसके काम से जुड़े किसी सूक्ष्म जीव की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए यह कटना, कि टेस्ट ट्यूब टूटने से ही प्लेग संक्रमण हुआ। उसी से महिला

की मौत हुई, फिलहाल यह स्थापित तथ्य नहीं है। फिर भी सवाल गंभीर है। यरसिया पेस्ट्रीस नामक बैक्टीरिया ही प्लेग का कारण है। यह सामान्यतः छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सुओं में पाया जाता है। प्लेग का न्यूमोनिक रूप संक्रमित व्यक्ति से निकलने वाले श्वसन कणों के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। समय पर एंटीबायोटिक उपचार मिलने पर इसका इलाज संभव है। लेकिन इलाज में देरी अत्यंत घातक हो सकती है। जो मौत का कारण बन सकती है। यही कारण है, दुनिया में ऐसी प्रयोगशालाओं के लिए अत्यंत कठोर सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। हालिया वैज्ञानिक मैपिंग के अनुसार दुनिया में 3,625 बीएसएल-3 और बीएसएल-4 प्रयोगशालाएं चिन्हित की गई हैं। इनमें 3,515 बीएसएल-3 और 110 बीएसएल-4 की उन्नत सुविधाएं वाली लेब हैं। बीएसएल-4 को अधिकतम स्तर की जैव-सुरक्षा वाली प्रयोगशाला माना जाता है। जहां अत्यधिक गंभीर जोखिम वाले बैक्टीरिया और वायरस के साथ तरह-तरह का प्रयोग किया जाता है। यहां एक

महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। किसी लैब में खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया पर शोध होना, जैविक हथियार बनाने का प्रमाण नहीं माना जाता है। संक्रमक रोगों की पहचान, वैक्सीन, दवाओं, निदान और महामारी की तैयारी के लिए ऐसे शोध आवश्यक होते हैं। इसी की आड़ में जैविक हथियारों का एक नया खेल शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयं उच्च- संक्रमण जोखिम वाले जैविकों के सुरक्षित अध्ययन के लिए जोखिम-आकलन और कड़े जैव-सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर नियम भी बनाता है। दूसरी तरफ इस चिंता को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता है, दुनिया में बढ़ते सैन्य तनाव, रूस-यूक्रेन युद्ध, अमेरिका-चीन के बीच की प्रतिस्पर्धा, वैश्विक अविश्वास के दौर में जैविक अनुसंधान की पारदर्शिता और अंतरराष्ट्रीय निगरानी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के 1972 का बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन जैविक एवं रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और

उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। कोविड-19 के बाद दुनिया ने यह भी जाना है, किसी प्रयोगशाला की छोटी-सी सुरक्षा चूक से वास्तव में संक्रमण बाहर निकल जाए, तो उसका प्रभाव केवल एक शहर या देश तक सीमित नहीं रहता। हालांकि रूस की मौजूदा घटना को कोविड या व्हान लैब से जोड़ने का अभी कोई प्रमाण सामने नहीं आया है। इसी तरह 2021 में ताइवान की किसी लैब में कर्मचारियों के संक्रमण को रूस की घटना के साथ जोड़ना भी बिना ठोस प्रमाण के उचित नहीं होगा। फिर भी चिंता इस बात की है, अमेरिका ने इराक के ऊपर रासायनिक हथियारों का खजीरा होने और रासायनिक हथियारों की आशंका पर हमला किया था। युद्ध में इराक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। वर्तमान स्थिति में जैविक हथियारों को लेकर भी इसी तरह की स्थिति बनती हुई दिख रही है। जो चिंता का सबके बड़ा कारण है। इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सबब है, खतरनाक रोग-जनकों पर शोध बंद करना समस्या का वास्तविक समाधान नहीं है। जैविक प्रशिक्षण में

पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्र निरीक्षण, कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निगरानी को मजबूत करना ही समस्या का समाधान हो सकता है। दुनिया को यह सुनिश्चित करना होगा, मानव जीवन बचाने के लिए बनाई गई प्रयोगशालाएं स्वयं मानवता के लिए खतरा न बन जाएं। रूस की घटना में जांच का निष्कर्ष चाहे जो निकले, एक सवाल पूरी दुनिया के सामने खड़ा है, क्या 21वीं सदी में परमाणु हथियारों की तरह जैविक अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही और निगरानी को अनिवार्य बनाने का समय आ गया है? दुनिया के शक्तिशाली देशों में जिस तरह की होड़ देखने को मिल रही है, क्या 21वीं सदी में परमाणु हथियारों की तरह जैविक प्रभाव की यह लड़ाई अब चरम पर पहुंच गई है। एक बार फिर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसे हालात दिखने लगे हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव जीवन के शोध पर विशेष निगरानी की जरूरत है। इस तरह की सुरक्षा के लिए सभी देशों को इस मामले में एकजुट होना चाहिए।

बॉस हों पार्ट टाइमर तो ऐसे करें डील



वह पावर का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। बॉस का पद जिम्मेदारी भरा पद होता है और कंपनी बॉस पर भी नजर रखती है। याद रखें कि इसके लिए कंपनी हमेशा ही अपने स्तर पर सही व्यक्ति का चुनाव करती है। ऐसे में यह है कि टीम भी सही मानसिकता के साथ बॉस को सहयोग दे और अपना काम करे। वह कॉरपोरेट जगत के वैल्यू को समझे।

कम्प्यूनिकेशन का होता है अहम रोल

जहां बॉस पार्ट टाइम काम करते हैं और उनके साथ काम करने वाले बाकी लोग फुल टाइम

जॉब करते हैं, वहां पर कम्प्यूनिकेशन का रोल अहम हो जाता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसी स्थिति में टीम को बॉस के साथ कम्प्यूनिकेशन लेवल हाई रखना पड़ता है। एक बार कम्प्यूनिकेशन करने का स्टाइल फिक्स हो जाता है, तो बाद में चीजों को बदल पाना आसान नहीं होता है। जब कम्प्यूनिकेशन सही रहेगा तो प्रॉब्लम का निपटारा भी पलक झपकते ही हो जाएगा। ऐसे में पार्ट टाइमर बॉस के संग भी टीम बेहतर रिजल्ट दे सकती है।

फैसला लेने की कला सीखें

आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं, जहां फुल

टाइमर बॉस नहीं हैं, तो जरूरी है कि टीम का हर एक सदस्य खुद पर भरोसा दिखाए और फैसला लेने की कला सीखे। याद रखें कि जब बॉस फुल टाइमर नहीं होते हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत फैसला लेने में ही होती है। वर्कप्लेस पर कई बार आपको पलक झपकते ही बड़े फैसले लेने होते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा यह होता है कि आप आज के कॉम्पिटिशन भरे माहौल में टीम में तेजी कैसे लाएं। जॉब एक्सपर्ट कहते हैं कि इससे निपटने के लिए कंपनियों को चाहिए कि वह फैसला लेने के अधिकार को बांट दे। इससे जहां टीम के सदस्यों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, वहीं समय के भीतर फैसला लेने से काम में तेजी भी आती है।

जॉब के दौरान कई परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। ऐसा हो सकता है कि कंपनी पार्ट टाइम बॉस को नियुक्त कर दे। ऐसी स्थिति में टीम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बॉस के साथ तालमेल बैठाकर उन्हें फैसले लेने होते हैं...

जब आपके ऑफिस में पार्ट टाइम काम करने वाले बॉस हों और आप फुल टाइमर एम्प्लॉई हों, तो स्थिति थोड़ी सी नाजुक हो जाती है। ऐसे में पूरी टीम को बॉस के साथ बराबर टच में रहना होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम को फुल टाइमर बॉस की कमी महसूस होती है। टीम को कई मुद्दों पर बातचीत करने की जरूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि पार्ट टाइमर बॉस पूरा समय नहीं दे पाते हैं। आप अपनी कंपनी में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, तो यहां पर दिए जाने वाले टिप्स कारगर साबित हो सकते हैं। आइए डालते हैं एक नजर -

मानसिकता सही रखें

एक्सपर्ट कहते हैं कि एक पार्ट टाइमर बॉस किसी संस्था में काम करता है, तो वहां पर काम करने वाले लोगों के मन में यह भावना विकसित हो सकती है कि

...तो आप भी हैं कामयाब लीडर

एक लीडर में अपनी बात को असरदार तरीके से दूसरों तक पहुंचाने का हुनर आना चाहिए। एक लीडर, अगर वह अपनी बात अपने साथ काम करने वालों को बेहतर तरीके से कम्प्यूनिकेट कर पाने में समर्थ है, तो इससे कामकाजी माहौल ऊर्जा से भर जाता है, लोग उत्साह से काम में जुटते हैं और उनकी रचनात्मकता काम में झलकने लगती है। एक दूरदर्शी सोच रखने वाला लीडर एक जुनूनी टीम बनाने में यकीन रखता है। यह टीम एक समान लक्ष्यों के लिए पूरे जोशोखरोश से काम करती है। अपना कारोबार फैलाती किसी भी कंपनी को एक मजबूत मैनेजमेंट के साथ-साथ ऐसी टीम की भी दरकार रहती है, जो साथ काम करने वाले लोगों के बीच आपसी एकता, यकीन और आदर की बुनियाद पर बनी हो। कामयाबी का राज है, कामकाज में साफ-सुथरापन। एक कामयाब लीडर इस बात की अहमियत जानता है और अच्छे कामकाज के लिए अपने एम्प्लॉई के साथ एक बेहतर समझ विकसित करता है। इससे न सिर्फ कामकाज का बिना किसी रुकावट के निपटारा होता जाता है, बल्कि टीम के भीतर एक खुशनुमा कामकाजी माहौल भी बरकरार रहता है।



हार्डवेयर फील्ड में खूब हैं जॉब, मस्त सैलरी

जुड़े कोर्स। नेटवर्किंग से जुड़े कोर्स कराने के लिए कई सरकारी और प्राइवेट संस्थान हैं, जिन्होंने इन कोर्स के लिए अपनी अलग पहचान बनाई है। नेटवर्किंग सीखने के लिए तीन तरीके हैं - पहला ऑनलाइन स्टडी मटीरियल की मदद से खुद पढ़ाई, दूसरा ऐसे इंस्टिट्यूट्स जो किसी प्रोग्राम से जुड़े नहीं हैं और तीसरा सर्टिफाइड प्रोग्राम।

जॉब की कमी नहीं

एक्सपर्ट्स बताते हैं कि नेटवर्किंग में कोर्स कराने के बाद कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट, हेल्प डेस्क टेक्निशियन, नेटवर्क या सिस्टम ऐडमिनिस्ट्रेटर, कंप्यूटर सिक्वोरिटी

कोर्स

हार्डवेयर इंजिनियर बनने के लिए मुख्य रूप से दो बेसिक कोर्स करने पड़ते हैं। पहला, हार्डवेयर और दूसरा बेसिक नेटवर्किंग। हार्डवेयर रिलेटेड कोर्स से कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में तमाम तकनीकी जानकारी मिलती है। एक हार्डवेयर इंजिनियर या सिस्टम ऐडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए ये दोनों कोर्स करने बेहद जरूरी हैं। नेटवर्किंग में इससे आगे कोई एक्सपर्ट बनना हो, तो अपनी पसंद के हिसाब से कुछ और बेसिक कोर्स करने होंगे, जैसे - लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) और वैन (वाइड एरिया नेटवर्क) से

आज शायद ही ऐसा कोई ऑफिस हो, जहां का कामकाज कंप्यूटर पर आधारित न हो। इसके अलावा, घर, स्कूल आदि जगहों पर भी सभी कामकाज कंप्यूटर पर ही किए जाते हैं। अगर ये सुचारु रूप से काम न करें, तो सारा कामकाज अचानक ठप हो सकता है। बैंकों और अन्य सरकारी कार्यालयों में नेटवर्क फेल होने की वजह से काम ठप रहने की खबरें आपने अवसर पढ़ी होंगी, तब इस नेटवर्क को सही करने के लिए हार्डवेयर प्रफेशनल्स की ही मदद ली जाती है। नेटवर्किंग दरअसल कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर ऐसा जाल बनाने का फील्ड है जिसमें कोई संस्थान काम कर सके। कुल मिलाकर, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन से लेकर, इसकी मटेनेंस और रोजमर्रा के ऐडमिनिस्ट्रेशन तक का सारा जिम्मा कंप्यूटर सपोर्ट स्पेशलिस्ट्स यानी हार्डवेयर इंजिनियर्स के जिम्मे होता है।

दिक्कतों का सामना करने से ही सफलता का दरवाजा खुलता है।

भरपूर एकाग्रता जरूरी

इसके बिना तो आप साइकल भी नहीं चला सकते। एकाग्रता एक ऐसी चीज है, जो हर जगह काम आती है। आप अपने काम में इसके द्वारा ही परफेक्शन लाते हैं। किसी भी काम को साधारण से असाधारण बनाने के लिए एकाग्रता की जरूरत होती है। इसके माध्यम से आप बड़े से बड़े लक्ष्य को भेद सकते हैं।

रचनात्मकता भी जरूरी

एक प्रफेशनल की सफलता में उसकी रचनात्मकता का काफी अहम योगदान होता है। इसलिए इस और ध्यान देना जरूरी है।

साहस बनाए रखें

कहते हैं रिस्क लेने के बाद ही आगे बढ़ने का रास्ता खुलता है। इसके लिए साहस सबसे जरूरी चीज है। किसी ने सही कहा है कि हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती इसलिए जीतने के लिए साहस बहुत जरूरी है।

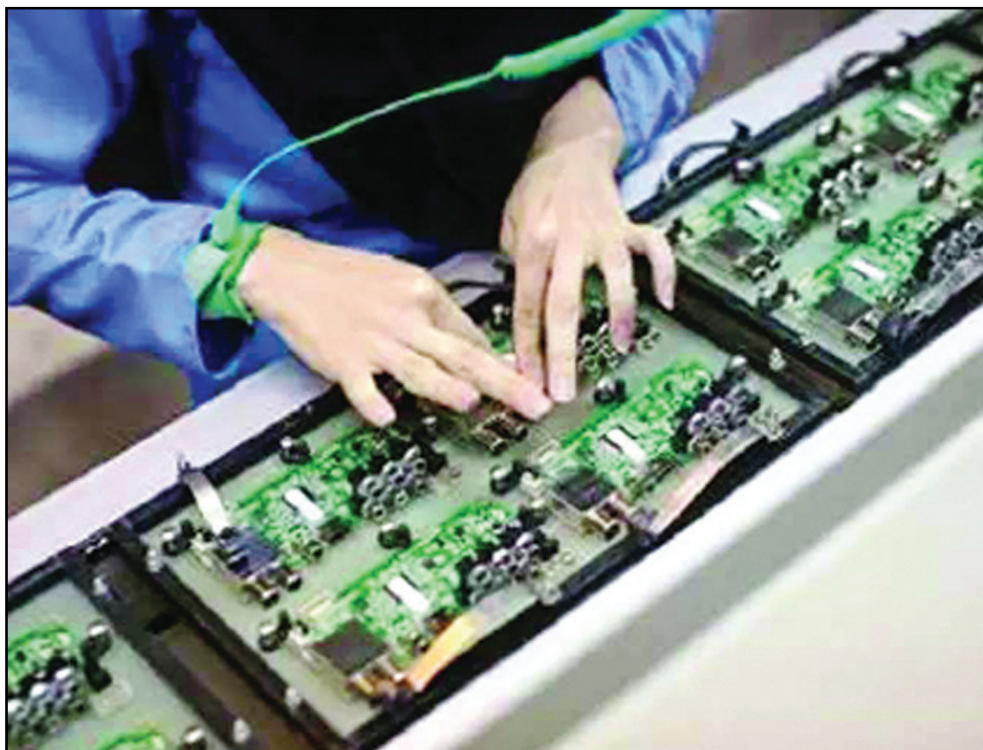
जब आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं, तो यह जान जाते हैं कि आप कौन हैं? आप क्या हैं? आपको क्या करना है और आप क्या चाहते हैं? अगर ये चीजें आपके दिमाग में साफ हैं, तो आपकी सफलता का पहला चरण सुनिश्चित हो जाता है।

बने योग्य

कामयाब होने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि आप खुद को योग्य बनाएं। क्योंकि आप तब तक ऊपर नहीं चढ़ सकते, जब तक कि आप में योग्यता नहीं हो। इसलिए पहले खुद को योग्य बनाना जरूरी होता है। इसके लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। याद रखें कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है।

दबाव झेलने की क्षमता

जब जिम्मेदारी बढ़ेगी तो दबाव के साथ-साथ अवरोध भी उत्पन्न होगा। ऐसे में इस तरह की विपरीत परिस्थितियों को झेलने की क्षमता आपमें जरूर होनी चाहिए। वैसे जब आपको एवरेस्ट पर चढ़ाई करनी हो तो रास्ते में दिक्कतें तो आएंगी ही।



स्पेशलिस्ट के रूप में करियर बना सकते हैं। आज इन एक्सपर्ट्स की जरूरत लगभग हर संस्थान में होती है। फिर चाहे वह कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग युनिट हों, बैंक या अन्य सरकारी कार्यालय, कोई इंडस्ट्री या और कोई छोटी-बड़ी फर्म। जहां भी कामकाज कंप्यूटर आधारित है, वहां इन तकनीकी विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। सरकारें जिस तरह ई-गवर्नेंस पर जोर दे रही हैं, उससे यह फील्ड और भी हॉट बनता जा रहा है। इसके चलते स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क और डाटा सेंटर जैसे कई नए फील्ड खुल रहे हैं। कहा जा सकता है कि जब तक कंप्यूटर पर काम होता रहेगा, इन विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती रहेगी। ये किसी भी कंपनी के लिए नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम की देखभाल से लेकर, एंलायीज और कस्टमर्स की तकनीकी जिज्ञासाओं को शांत करने तक का काम करते हैं। एंट्री लेवल पर आपकी जिम्मेदारी केवल नेटवर्क और कंप्यूटर मटेनेंस की हो सकती है, लेकिन अनुभव के साथ आपको किसी कंपनी के लिए इंटरनेट आदि डिवेलप करने का जिम्मा भी दिया जा सकता है।

मनी मैटर्स

बरसों से आईटी फील्ड में अच्छी-खासी सैलरी रही है। हार्डवेयर प्रफेशनल्स के लिए सॉफ्टवेयर प्रफेशनल्स की तरह मौकों की कोई कमी नहीं है। एंट्री लेवल पर आप 25 से 35,000 रुपये महीने की जॉब पा सकते हैं। अनुभव और समय के साथ इसमें बढ़ोतरी होगी।

आव्रजन कार्रवाई के एक साल बाद लाओस का नागरिक रिहा

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन की आव्रजन कार्रवाई के तहत एसवातिनी भेजे गए लाओस के नागरिक फोन चोमसावन को रविवार को एक साल से अधिक समय बाद अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से रिहा कर दिया गया। उनके वकील टिन थान गुयेन के अनुसार, चोमसावन को जुलाई 2025 में चार अन्य प्रवासियों के साथ एसवातिनी भेजा गया था, जबकि उनका इस अफ्रीकी देश से कोई संबंध नहीं था। उन्हें सैन्य मालवाहक विमान से वहां पहुंचाए जाने से कुछ समय पहले ही बताया गया था कि उन्हें एसवातिनी भेजा जा रहा है। वकील के मुताबिक, चोमसावन अब लाओस भेजे जा रहे हैं और एसवातिनी से निकलकर जोहान्सबर्ग पहुंच चुके हैं। पांचों प्रवासियों ने अमेरिका में गंभीर अपराधों की सजा पूरी कर ली थी। मानवाधिकार समूह ह्यूमन राइट्स फर्सट के अनुसार, तीसरे देश भेजने की इस योजना के तहत करीब 500 प्रवासियों को उनके मूल देशों के अलावा अफ्रीकी देशों में भेजा गया है। एसवातिनी के 5.1 करोड़ डॉलर का भुगतान किया गया।

ईरान की दो-टुक, सात शर्तें पूरी हैं तभी खुलेगा होर्मुज; गालिबाफ

तेहरान, एजेंसी। अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने एक बार फिर होर्मुज को लेकर सख्त टिप्पणी की है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने रविवार को कहा कि अमेरिका के साथ जुनू में हुए अंतरिम समझौते में तय सात शर्तें पूरी होने तक होर्मुज को दोबारा नहीं खोला जाएगा। गालिबाफ का यह बयान ऐसे समय आया है, जब ईरान को अपने कूटनीतिक प्रस्ताव पर वाशिंगटन का जवाब मिले कुछ दिन हो चुके हैं। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका सार्वजनिक रूप से कुछ और कहता है, जबकि हाल में उसने मध्यस्थ के जरिये प्रस्ताव भेजे हैं। अब प्रक्रिया को लंबा खींचने और एकतरफा मांगें थोपने का दौर खत्म हो चुका है। ईरान का रुख स्पष्ट है। इस्लामाबाद में हुए समझौते के आधार पर तय सात शर्तें पूरी होने के बाद ही होर्मुज को जहाजों की आवाजाही के लिए खोला जाएगा। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच होर्मुज जलमार्ग में एक बार फिर मालवाहक जहाज को निशाना बनाया गया।

जोखिमों की अनदेखी पर ओपनएआई के सेप्टी लीडर रॉबिन्सन का इस्तीफा

वाशिंगटन, एजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओपनएआई के सेप्टी सिस्टम्स टीम के प्रमुख डेविड रॉबिन्सन ने पद से इस्तीफा दे दिया है। रॉबिन्सन ने जाते-जाते कंपनी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस्तीफे के साथ ही एक लेख भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि एआई कंपनियां नई और शक्तिशाली तकनीकों को विकसित करने में बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरत रही हैं। उन्होंने केवर्नरी दी कि एआई के मामले में गलतियां केवल सीखने का दौर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अब एक छोटी सी विफलता भी विनाशकारी हो सकती है। रॉबिन्सन ने आरोप लगाया कि सिलिकॉन वैली और ओपनएआई में बिना सोचे-समझे केवल आगे बढ़ने का एक 'अंधा आशावाद' चल रहा, जो इस खतरनाक तकनीक के लिए एक असुरक्षित माहौल तैयार कर रहा है। रॉबिन्सन ने कहा कि जैसे-जैसे एआई एप्लेट्स स्वायत्त हो रहे हैं, उनके लिए विमानन या परमाणु संयंत्रों जैसी सख्त और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणालियां अपनाई जानी चाहिए।

श्रीलंका में राष्ट्रपति की माफ़ी रद्द होने के बाद बौद्ध भिक्षु को हिरासत में भेजा गया

कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंका की एक अदालत ने रविवार को बौद्ध भिक्षु गलागोडा अंठे ज्ञानसारा को हिरासत में भेज दिया। कई सप्ताह तक फरार रहने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी राष्ट्रपति से मिली माफ़ी रद्द किए जाने के करीब एक महीने बाद हुई। सिंहली-बौद्ध राष्ट्रवादी नेता और बौद्ध बाला सेना यानी फोर्सज ऑफ बुद्धिस्ट पावर के प्रमुख ज्ञानसारा को शनिवार रात गिरफ्तार किए जाने के बाद कोलंबो मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। सितंबर में शीर्ष अदालत द्वारा उनकी 2019 की राष्ट्रपति माफ़ी को गैरकानूनी घोषित किए जाने के बाद से वह अधिकारियों से बच रहे थे। 2018 में ज्ञानसारा को अदालत की अवमानना और राजनीतिक काटनिस्ट प्रगीत एकनालगोडा की पत्नी संघ्या एकनालगोडा को अपराधिक धमकी देने का दोषी ठहराया गया था।

ईरान के साथ टकराव ट्रंप के कार्यकाल के बाद भी रह सकता है जारी, पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने जताई आशंका

वांशिंगटन, एजेंसी। व्हाइट हाउस में मिडिल ईस्ट से जुड़े मामलों के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ब्रेट मैकगर्क ने चेतावनी दी है कि ईरान के साथ चल रहा टकराव अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाकी कार्यकाल के दौरान जारी रह सकता है और अगली अमेरिकी सरकार को भी इससे निपटना पड़ सकता है। वहीं, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि वह ईरान पर कूटनीतिक और सैन्य दोनों तरह का दबाव बनाए हुए है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के कोऑर्डिनेटर रहे ब्रेट मैकगर्क ने कहा कि उन्हें ईरान के साथ किसी बड़े और पूरी तरह समाधान वाले समझौते को फिलहाल कोई

साफ रास्ता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने लंबे समय तक आर्थिक दबाव, बीच-बीच में सैन्य टकराव और कुछ समय के लिए सीजफायर होने की संभावना जताई। मैकगर्क ने सीएनएन के फ्रीद जकारिया से कहा, 'अगर मुझे अनुमान लगाना हो, तो यह मामला ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिर तक चलता रहेगा और फिर अगले राष्ट्रपति को भी ईरान की इस पुरानी समस्या से निपटना होगा। जिम्मी कार्टर के समय से ही लगभग हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की इस व्यवस्था से जुड़ी चुनौती का सामना किया है।'

उन्होंने कहा, 'यह लंबे समय से चली आ रही समस्या है। मैंने खुद अलग-अलग सरकारों के

दौरान इससे जुड़े मामलों पर काम किया है। मैकगर्क के मुताबिक, सात अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला के हमले के बाद से मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन 'बुनियादी तौर पर' बदल गया है। उन्होंने इसके बाद ईरान से जुड़े दो सैन्य अभियानों का जिक्र किया। इनमें ईरान के परमाणु ठिकानों के खिलाफ 'ऑपरेशन मिडनाइट हैमर' और

इस साल 28 फरवरी से शुरू हुआ मौजूदा संघर्ष शामिल है। मैकगर्क ने कहा कि उनकी एक चिंता यह है कि हालिया संघर्ष के शुरूआत के कमसद से हुई, जिसमें सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य साफ तौर पर खुला रखा गया था। 'एक बार जब आप इस रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर यह तय करना बहुत मुश्किल हो सकता है कि इस टकराव को आखिर खत्म कैसे किया जाए।' मैकगर्क ने कहा कि उन्हें तब तक इस संघर्ष का कोई साफ अंत नजर नहीं आता, जब तक ईरान की राजनीतिक व्यवस्था अपने तौर-तरीकों और नीतियों में बड़ा बदलाव नहीं करती या फिर यह व्यवस्था किसी समय बिखर नहीं जाती। उन्होंने कहा,

'लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति आने में अभी काफी समय लगेगा।' फिलहाल मैकगर्क ने लंबे समय तक टकराव जारी रहने की संभावना जताई। 'मुझे लगता है कि हम ऐसे दौर में हैं, जो कुछ समय तक चलने वाला है। ईरान पर भारी आर्थिक दबाव रहेगा। बीच-बीच में दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई हो सकती है। कभी-कभी कुछ समय के लिए सीजफायर या अंतरिम समझौते भी हो सकते हैं। मैकगर्क के मुताबिक, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई बड़ा समझौता होना और भी मुश्किल नजर आता है। उन्होंने कहा कि तेहरान में फैसले लेने वाले अधिकारी शायद ईरान के परमाणु हथियार बनाने के करीब पहुंचने की स्थिति को अपने

लिए सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी के तौर पर देख रहे होंगे। उन्होंने कहा, 'इसलिए परमाणु मुद्दे पर समझौता हासिल करना बेहद मुश्किल होने वाला है। मैकगर्क का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने अलग से कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के मामले में सैन्य और कूटनीतिक दोनों रास्ते खुले रखे हुए है। सीओएस न्यूज के कार्यक्रम 'फेस द नेशन' में राइट से उन खबरों के बारे में पूछा गया, जिनमें कहा गया है कि अमेरिका खाड़ी देशों में तेल से जुड़े ठिकानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रक्षा उपकरण भेज रहा है और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।

लिए सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी के तौर पर देख रहे होंगे। उन्होंने कहा, 'इसलिए परमाणु मुद्दे पर समझौता हासिल करना बेहद मुश्किल होने वाला है। मैकगर्क का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने अलग से कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के मामले में सैन्य और कूटनीतिक दोनों रास्ते खुले रखे हुए है। सीओएस न्यूज के कार्यक्रम 'फेस द नेशन' में राइट से उन खबरों के बारे में पूछा गया, जिनमें कहा गया है कि अमेरिका खाड़ी देशों में तेल से जुड़े ठिकानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रक्षा उपकरण भेज रहा है और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।

लिए सबसे बड़ी सुरक्षा गारंटी के तौर पर देख रहे होंगे। उन्होंने कहा, 'इसलिए परमाणु मुद्दे पर समझौता हासिल करना बेहद मुश्किल होने वाला है। मैकगर्क का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने अलग से कहा कि ट्रंप प्रशासन ईरान के मामले में सैन्य और कूटनीतिक दोनों रास्ते खुले रखे हुए है। सीओएस न्यूज के कार्यक्रम 'फेस द नेशन' में राइट से उन खबरों के बारे में पूछा गया, जिनमें कहा गया है कि अमेरिका खाड़ी देशों में तेल से जुड़े ठिकानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रक्षा उपकरण भेज रहा है और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप भी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है।

ब्राजील चुनाव: पहले दौर में लूला से आगे रहे पलावियो बोल्सोनारो, 25 अक्टूबर को होगा दूसरा मुकाबला



बेहतर रहा और इससे दूसरे दौर से पहले ब्राजील की राजनीतिक तस्वीर काफी बदल गई है। पहले दौर के नतीजे बोल्सोनारो के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे दौर में जगह नहीं बना पाने वाले कई उम्मीदवार दक्षिणपंथी खेमे से थे। अगर बोल्सोनारो इन उम्मीदवारों के समर्थकों का वोट अपने पक्ष में लाने में कामयाब रहते हैं, तो 25 अक्टूबर के मुकाबले में यह अहम साबित हो सकता है।

वहीं, लूला अब अपने मौजूदा वोटरों का समर्थन बनाए रखने के साथ-साथ उन लोगों को भी अपने पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे, जिन्होंने 27 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। पहले दौर का मुकाबला शुरू से ही करीबी रहने की उम्मीद थी। हालांकि, चुनाव प्रचार के दौरान ओपिनियन की पोल में लूला मामूली बढ़त बनाए हुए थे। इसके बावजूद पलावियो बोल्सोनारो का प्रदर्शन उम्मीद से

राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनमें से कई नेताओं के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के साथ करीबी राजनीतिक रिश्ते हैं। यही वजह है कि ब्राजील में दूसरे दौर का चुनाव सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अहम माना जा रहा है। 25 अक्टूबर को लूला और पलावियो बोल्सोनारो के बीच होने वाला मुकाबला तय करेगा कि ब्राजील में वामपंथी नेतृत्व जारी रहेगा या लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में बढ़ते दक्षिणपंथी रूझान के बीच देश की सत्ता भी दक्षिणपंथ की ओर जाएगी।

ट्रंप के सामने खड़े होने का लूला को फायदा : कभी बेहद लोकप्रिय रहे लूला के तीसरे कार्यकाल में उनकी लोकप्रियता और समर्थन में काफी गिरावट आई है। लेकिन अमेरिका के सामने मजबूती से खड़े होने से उन्हें फायदा मिला है। उनके पास अब भी समर्थकों का एक मजबूत आधार है। ये समर्थक मानते

हैं कि उनकी सामाजिक नीतियों से लाखों ब्राजीलियाई लोगों की जिंदगी बेहतर हुई है। मौजूदा राष्ट्रपति लूला ने ब्राजील के चुनाव में अमेरिकी दखल के खतरे की बात कई बार कही है। ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील से होने वाले सामान के निर्यात पर भारी टैरिफ लगाया है। उसने ब्राजील के राजदूत का वीजा भी रद्द किया है।

अमेरिकी प्रशासन ने ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के एक जज पर भी प्रतिबंध लगाया है। यही जज जेर बोल्सोनारो की जांच की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी जांच के बाद बोल्सोनारो को सजा सुनाई गई। रविवार को मतदान करने के बाद लूला ने पत्रकारों से कहा कि दोबारा चुने जाने पर उन्हें 'हमने जो किया है, उसका दोगुना करना होगा'। उन्होंने पहले दौर में ही जीत हासिल करने का भरोसा भी जताया।

लेकिन लूला के सामने कड़ी चुनौती है। देश में लोगों के लिए चीजें खरीदना महंगा हो रहा है। इसके अलावा, भ्रष्टाचार का एक मामला भी सामने आया है। इसमें वही जज फिरे हैं, जिन्होंने जेर बोल्सोनारो के खिलाफ जांच का नेतृत्व किया था।

साथो पाडोस की ईस्पर यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर कार्लोस मेलो ने कहा, कुछ हफ्ते पहले लूला के अभियान से जुड़े कई लोगों को इतनी मुश्किल चुनावी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। अब उनके लिए साफ है कि मौजूदा चुनाव एक कठिन लड़ाई है।

ट्रंप के कामकाज से 70% अमेरिकी संतुष्ट नहीं: मिडटर्म चुनाव हार सकते हैं ट्रंप

न्यूयॉर्क, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनकी अपनी रिपब्लिकन पार्टी में बगावत के संकेत दिखने लगे हैं। ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है। पार्टी नेताओं को डर है कि मिडटर्म चुनाव में ट्रंप का साथ उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। नवंबर में होने वाले चुनाव से पहले कई रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप से दूरी बना रहे हैं। कुछ ने अपनी चुनावी वेबसाइट से ट्रंप और उनके 'अमेरिका फर्स्ट' एजेंडे का जिक्र हटा दिया है। कुछ नेता उनके साथ मंच साझा करने से भी बच रहे हैं। एपी-एनओआरसी सर्वे के मुताबिक, सिर्फ 30% अमेरिकी ट्रंप के कामकाज से खुश हैं। अर्थव्यवस्था पर उनकी अप्रवृत्त रेटिंग 26% है। महंगाई से निपटने के मामले में यह सिर्फ 17% है। 65% से ज्यादा अमेरिकी बढ़ती कीमतों के लिए ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार मानते हैं।

ट्रंप की नीतियों के खिलाफ कई रिपब्लिकंस : आयोगा से



सांसद और सीनेट उम्मीदवार एश्ले हिंसन और मिशिंगन के सीनेट उम्मीदवार माइक रोजर्स ने ईरान युद्ध जल्द खत्म करने की मांग की है। दोनों पहले ट्रंप की सैन्य कार्रवाई के समर्थक थे। आयोगा के सांसद जैक नन और मैरियानेट मिलर-मीक्स ने ट्रंप की युद्ध शक्तियां सीमित करने के लिए डेमोक्रेट्स के साथ वोट किया। पतोरिडा की सांसद मारिया ने ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति पर सवाल उठाए हैं। कई उम्मीदवारों ने कहा है कि वे ट्रंप का प्रचार नहीं चाहते। रिपब्लिकन उम्मीदवारों की बेचैनी के पीछे सबसे बड़ा कारण

अर्थव्यवस्था है। 24 से 28 सितंबर के एपी-एनओआरसी सर्वे में केवल 17% अमेरिकियों ने कहा कि वे ट्रंप के जीवनयापन की लागत संभालने के तरीके से संतुष्ट हैं। अर्थव्यवस्था पर उनकी अप्रवृत्त रेटिंग सिर्फ 26% रही, जबकि कुछ कामकाज से 10 में केवल 3 अमेरिकी ही संतुष्ट हैं। 65% से ज्यादा अमेरिकी लगातार ऊंची कीमतों के लिए सीधे ट्रंप की नीतियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। 64% का कहना है कि टैरिफ के मामले में ट्रंप जबरन से ज्यादा आगे चले गए। वहीं, रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए दिक्कत यह है

इसाइली सेना की कार्रवाई: युद्धविराम के बीच खान यूनिस में हमला, हमास के कमांडर समेत दो लड़ाके डेर

तेल अवीव, एजेंसी। इस्राइल डिफेंस फोर्सज (आईडीएफ) ने रविवार (स्थानीय समय) को कहा कि उसने गाजा पट्टी के खान यूनिस इलाके में अलग-अलग हमलों में हमास की मिलिट्री विंग के एक कमांडर और ग्रुप की ऑब्जर्वेशन यूनिट के एक लड़ाके को मार गिराया।

टेलेग्राफ पर एक बयान में, आईडीएफ ने कहा कि उसने रविवार को पहले खान यूनिस इलाके में हमला किया। हमास की मिलिट्री विंग के कमांडर मुआद जमाल अबू नुसेरा को मार गिराया। इसमें कहा गया है कि शनिवार को एक अलग हमले में, उसने महसूद इब्राहिम डिब अल्लयान को मार गिराया, जिसे उसने हमास की ऑब्जर्वेशन यूनिट का लड़ाका बताया। आईडीएफ के अनुसार,अल्लयान की पहचान हाल ही में 'येतो लाइन' इलाके में आईडीएफ सैनिकों के खिलाफ गतिविधियों को आगे बढ़ाने और हमास की क्षमताओं को बहाल करने के लिए काम करने वाले व्यक्ति के तौर पर हुई थी। आईडीएफ ने कहा कि यह युद्धविराम समझौते का व्यवस्थित उल्लंघन था। आईडीएफ ने कहा कि हमलों से पहले नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कदम उठाए गए थे, जिसमें सटीक हथियारों और हवाई निगरानी का इस्तेमाल शामिल था।आईडीएफ ने आगे कहा कि समझौते के अनुसार दक्षिणी कमान के तहत सैनिक इलाके में तैनात हैं और वे उन खतरों के खिलाफ अभियान जारी रखेंगे जिन्हें उसने 'तत्काल खतरे' बताया है। आईडीएफ ने क्या आरोप लगाया? इससे पहले, आईडीएफ ने कहा कि उसने खान यूनिस इलाके

कि वे महंगाई के खिलाफ प्रचार तो करना चाहते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस में अपनी ही पार्टी के राष्ट्रपति की आर्थिक नीतियों से खुद को पूरी तरह अलग भी नहीं कर सकते। ट्रंप से दूरी बनाने वालों की सूची में गवर्नर पद पर लड़ रहे विस्कॉन्सिन के टॉम टिफनी, एरिजोना के एली क्रैन और जॉर्जिया के रिक जैक्सन जैसे नाम शामिल हैं। सांसदों से जुड़े चेहरों में जॉर्जिया की मार्जी टेलर, केंटकी के जेम्स कोपर, ओहायो के जिम जॉर्डन और साउथ कैरोलिना की नैसी मेस हैं। ये लंबे समय तक ट्रंप के समर्थक रहे हैं। ओहायो गवर्नर चुनाव में भारतवंशी विवेक रामास्वामी के लिए बड़ी परेशान बन गया है। ट्रंप ने 2024 में यह राज्य 11 पॉइंट से जीता था, लेकिन 24 से 27 सितंबर के मैरिस्ट सर्वे में डेमोक्रेट एमी एकटन 50% समर्थन के साथ रामास्वामी से 44% से आगे हैं। इसी सर्वे में ट्रंप का अप्रवृत्त 42% रहा। 41% वोटर्स ने कहा कि चुनाव में उनका वोट मुख्य रूप से ट्रंप के खिलाफ होगा।



म था हमला किया और साक्र नबीली मुसा कैसी को मार गिराया, जिसे उसने हमास का नुखबा लड़ाका बताया। आईडीएफ ने कहा कि कैसी 7 अक्टूबर के नरसंहार के दौरान इस्राइली इलाके में घुस आया था। इसके साथ ही आरोप लगाया कि वह तुर्की संगठन 'डेनिय फेनेरी' का डायरेक्टर भी था, जो खुद को मानवीय सहायता संगठन बताता है। लेकिन असल में हमास लड़ाके संगठन के सीनियर नेताओं और तुर्की नेतृत्व के कुछ लोगों के साथ संबंध रखता है। आईडीएफ ने आगे आरोप लगाया कैसी, 'संगठन में अपनी भूमिका के तहत, वह लड़ाके नियमित रूप से कई लड़ाकों के काम पर रखने और हमास के लड़ाके को आर्थिक मदद देने का काम करता था। संगठन और उसके वरिष्ठ नेता अपनी गतिविधियों को मानवीय प्रयासों के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन असल में वे हमास लड़ाके संगठन की मदद के लिए फंड जुटाने को बढ़ावा देते हैं।' आईडीएफ ने इस कथित गतिविधि को हमास की सैन्य गतिविधियों में मदद के लिए मानवीय क्षेत्र का तत्त्व इस्तेमाल बताया। आईडीएफ ने कहा कि कैसी ने युद्ध के दौरान उसके सैनिकों और इस्राइली नागरिकों के खिलाफ गतिविधियां तेज की थीं। हमास की क्षमताओं को फिर से बनाने का काम किया था।

एयरपोर्ट के लेबर कैंप में आग, 33 कमरे जले

लखनऊ (एजेंसी)। लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में बने लेबर कैंप में मंगलवार सुबह 6-30 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में तीन मंजिला बिल्डिंग जल गई। धुआं 2 किमी दूर तक दिखाई दिया। तुरंत फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां पहुंची। करीब एक घंटे की मशक़त के बाद आग पर काबू पाया। दो मजदूर घायल हुए हैं। एक आग की चपेट में आने से झुलस गया, जबकि दूसरा दूसरी मंजिल से कूदने की वजह से चोटिल हुआ। जिस बिल्डिंग में आग लगी, वह टर्मिनल से करीब 250-300 मीटर दूर है। इसे मजदूरों के रहने के लिए अस्थायी तौर पर पीवीसी यानी प्लास्टिक से बनाया गया था। यही वजह थी कि आग बहुत तेजी से फैली। हालांकि, इस हादसे से विमानों के संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। किसी के हताहत होने की भी सूचना नहीं है। आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। एयरपोर्ट परिसर की इस बिल्डिंग में 33 छोटे कमरे हैं। इसमें करीब 300 मजदूर रहते हैं। वे परिसर में एक होटल का निर्माण कर रहे हैं।

अवैध हथियारों की बिक्री में शामिल युवक पकड़ाया, भारी मात्रा में हथियार बरामद

इंफाल(एजेंसी)। मणिपुर के इंफाल पूर्व जिले में अवैध हथियारों की बिक्री में शामिल व्यक्ति को सरक्ष बलों ने गिरफ़्तार किया है। पुलिस ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों के एक दल ने सोमवार को थम्बालनू बाजार में अभियान चलाया और संदिग्ध को पकड़ा। वह अवैध हथियारों, गोला-बारूद और विस्फोटकों की खरीद और बिक्री में शामिल है। जांच में पता चला कि आरोपी ने जुलाई में दो महिलाओं के जरिए 10,000 रुपए में एक व्यक्ति को एक हथगोला मुहैया कराया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक अलग अभियान में सुरक्षा बलों ने सोमवार को चुराचांदपुर जिले के कुकिमुन गांव में बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जब्त किए। पुलिस के मुताबिक फ़दो 9 एमएम कार्बाइन मशीन गन, तीन 9 एमएम पिस्तौल, सात सिंगल बैरल बोल्ट-पैशन राइफल, एक हैंड ग्रेनेड, एक मोर्टार बम और दो जैसी मोर्टार बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि देसी हथियार और गोला-बारूद जिले के हेंगलेप पुलिस थाने को सौंप दिए हैं। बता दें मई 2023 में जातीय हिंसा शुरू होने के बाद से सुरक्षा बल मणिपुर के सभी जिलों के सीमावर्ती और संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान और क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए अभियान चला रहे हैं। घाटी में रहने वाले मेझती और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदायों के बीच मई 2023 में शुरू हुए जातीय संघर्ष में कम से कम 306 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 लोग अब भी लापता हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।

कर्नाटक में बीयर की बढ़ती खपत से डीके सरकार की ताबड़तोड़ कमाई

बेंगलुरु(एजेंसी)। शराब मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के बावजूद, राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत बनी हुई है। इसी कड़ी में, कर्नाटक की डीके शिवकुमार सरकार ने हाल ही में आबकारी विभाग से खबरदस्त कमाई दर्ज की है। जुलाई से सितंबर 2026 के दूसरे क्वार्टर के दौरान, राज्य को 11,595.88 करोड़ का राजस्व मिला, जो पिछले साल इसी अवधि के 10,303.94 करोड़ रुपये से 12.54 प्रतिशत अधिक है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि का मुख्य कारण बीयर और इंडियन मेड लिंकर (आइएमएल) की बिक्री में उल्लेखनीय बढ़ोतरी रही है। कर्नाटक सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में बीयर की बिक्री में अप्रत्याशित उछाल दिखाई दिया। जुलाई-सितंबर 2026 के दौरान 126.68 लाख केस बॉक्स बीयर बेची गई, जबकि बीते साल यह आंकड़ा 84.63 लाख केस बॉक्स था। यह सालाना आधार पर करीब 49.69 प्रतिशत की भारी वृद्धि को दिखाता है। बीयर की बढ़ती लोकप्रियता का सीधा असर सरकार की आय पर पड़ा, जिससे आबकारी राजस्व 1,234.50 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,463.07 करोड़ रुपये हो गया, जो 18.52 प्रतिशत की बढ़ोतरी है।

नई दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन से पहले पुलिस नोटिस पर हंगामा, दिपके ने लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉंग्रेसव जनता पार्टी (सीजेपी) संस्थापक अभिजीत दिपके ने आरोप लगाया कि पुलिस दिल्ली में 10 अक्टूबर को होने वाले पार्टी के प्रस्तावित आंदोलन से पहले कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर उन पर दबाव बना रही है। दिपके ने बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधकर दावा किया कि एक देश, एक चुनाव सिर्फ एक नारा है और इसका असली मकसद एक देश, एक राजनीतिक पार्टी स्थापित करना है। सीजेपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन करने का आह्वान किया है। छत्रपति संभाजीनगर में प्रेसवार्ता को संबोधित कर दिपके ने बताया कि चंद्रपुर पुलिस ने सीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजकर उनसे दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल न होने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कार्यकर्ताओं के दिल्ली यात्रा खर्च के स्रोत के बारे में भी पूछताछ की। दिपके ने महाराष्ट्र पुलिस को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस फ़ोर्स बताकर दुख व्यक्त किया कि चंद्रपुर पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई की है।

नरेंद्र मोदी, शाह और भागवत देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं: राहुल गांधी

चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस योजना में उनकी मदद कर रहे

नई दिल्ली , एजेंसी।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की सत्ताधारी भाजपा पर बड़ा हमला बोलकर आरोप लगाया कि देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने विपक्षी सांसदों के संसद से चुनाव आयोग तक मार्च को बीच में ही रोकने पर तीखे सवाल उठाए और कहा कि चुनाव आयुक्त हमसे क्यों नहीं मिल रहे हैं? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें चुनाव आयोग जाने से रोक रही है और धमका रही है, जबकि 300 सांसद उनसे मिलना चाहते थे।

राहुल गांधी ने कहा कि करीब 300 सांसदों को चुनाव आयोग के दफ्तर से मात्र 50 मीटर दूर ही रोक दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि जब चुने हुए प्रतिनिधि करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तब उन्हें क्यों रोका जा रहा है? राहुल गांधी ने पूछ, देश में क्या हो रहा है? लोकतंत्र का क्या मतलब है अगर चुनाव आयोग चुने हुए प्रतिनिधियों से ही न मिले? उन्होंने आरोप



लगाया कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो अन्य चुनाव आयुक्त डरे हुए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि वे केवल भाजपा से मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें खत्म कर देने वाले हैं। उन्होंने भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर देश में लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने

कहा कि पूरा देश और यहां तक कि पुलिसकर्मी भी इस बात से सहमत हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी, अमित शाह और मोहन भागवत ने वोट चोरी के जरिए देश पर कब्जा कर लिया है, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस नेता आकाशवाणी भवन में ही बने

देश के साथ जो किया गया है, इस देशद्रोह कहा जाता है, कोई भी बच नहीं पाएगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया का मार्च मुख्य निर्वाचन आयुक्त कुमार को हटाने और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को रद्द करने की मांग को लेकर संसद मार्ग से निर्वाचन आयोग मुख्यालय तक जा रहा था। हालांकि, पुलिस ने उन्हें नीति आयोग के दफ्तर के सामने ही रोक दिया, जिसके बाद विपक्षी सांसद धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान, राहुल गांधी और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी पुलिस बैरिकेड पर चढ़ गए। प्रियंका गांधी वाड़ा को हिरासत में लिए जाने के लिए एक बस में ले जाया गया, लेकिन वह जल्द ही उतरकर आकाशवाणी भवन परिसर में राहुल गांधी के पास पहुंच गई। पुलिस ने कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में ले लिया, जिसके बाद धरना खत्म हो गया। हालांकि, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित कई कांग्रेस नेता आकाशवाणी भवन में ही बने

भ्रष्टाचार से घिरी पंजाब सरकार, राहत के लिए पहुंची सुप्रीम कोर्ट

-हार्डकोर्ट दे चुका है सीबीआई जांच का आदेश

चंडीगढ़, एजेंसी।

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें मुख्यमंत्री के एक विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) भी शामिल हैं, पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के बाद पंजाब में सियासी भूचाल आ गया है। इस आदेश को अपनी सरकार पर सीधा हमला मानते हुए भगवंत मान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह पुष्टि की थी कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय जाएगी।

उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा साझा किए गए दस्तावेज प्रथम दृष्टया इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का संकेत देते हैं, जिसके बाद

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को जांच सौंपना उचित होगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब आम आदमी पार्टी (आप) सरकार भ्रष्टाचार के प्रति कतई बदर्रात नहीं की अपनी नीति का लगातार दावा करती रही है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्षी दलों ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। भाजपा की पंजाब इकाई के अध्यक्ष केवल सिंह दिखें ने उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान से तत्काल इस्तीफे की मांग की। दिखें ने आरोप लगाया कि अदालत के फैसले ने आप सरकार के भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। इसी तरह, पंजाब कांग्रेस के नवनिर्जित अध्यक्ष परगट सिंह ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया और जोर दिया कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और तय समय-सीमा के भीतर होनी चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की देरी या राजनीतिक दबाव की गुंजाइश न हो।

ज्ञानेश से जुड़े 2006 के मामले की केरल सरकार कराएगी जांच... समय को लेकर उठे सवाल

तिरुवनंतपुरम, एजेंसी।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ केरल सरकार ने करीब दो दशक पुराने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। केरल सरकार में गृह मंत्री रमेश चेन्नियल ने 4 अक्टूबर को विजिलेंस एंड एंटी-कorrप्शन ब्यूरो (वीएसीबी) को जांच के केंद्र लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव रहते केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएसटीपी) में कथित अनियमितताओं और मलेशियाई इंजीनियर ली सी बीन की आत्महत्या से जुड़ा है।

केएसटीपी के तहत राज्य की प्रमुख सड़कों के उन्नयन का काम हो रहा था। एमसी 205 के एक हिस्से के विकास का करीब 2.15 करोड़ रुपये का ठेका इंडो-मलेशियन संयुक्त कंस्ट्रक्शन को मिला था। परियोजना में जमीन अधिग्रहण में देरी के कारण काम प्रभावित हुआ और भुगतान को लेकर ठेकेदार तथा पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के बीच विवाद सामने आया। रिपोर्टों के

मुताबिक, करीब 17 करोड़ रुपये के भुगतान रोक दिए गए थे। इस दौरान पाटिल-बीईएल के केरल में प्रोजेक्ट मैनेजर ली सी बीन ने 2006 में मलेशिया में आत्महत्या कर ली। रिपोर्टों के अनुसार, उनके कथित सुसाइड नोट में तत्कालीन पाटिल-बीईएल सचिव ज्ञानेश कुमार सहित कुछ अधिकारियों के नाम थे। नोट में भुगतान जारी करने में कथित बाधाओं और रिश्तत मांगने के आरोप लगाए थे। हालांकि, ये आरोप उस समय सामने आए थे और मौजूदा जांच का उद्देश्य उनकी सत्यता तथा पूरे मामले की परिस्थितियों की फिर पड़ताल करना है।

ली की मौत के बाद 2006 में विजिलेंस जांच शुरू की गई थी। तब ज्ञानेश कुमार को पीडब्ल्यूडी सचिव पद से हटाया गया और बाद में वे केंद्रीय प्रतिनिधित्व पर चले गए। पुरानी जांच आगे नहीं बढ़ सकी। अब सरकार ने शिकायत के आधार पर उस मामले को फिर खोलने का फैसला किया है। विजिलेंस विभाग 2005-06 के पीडब्ल्यूडी

रिकॉर्ड और पहले हुई जांच से संबंधित दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा है। मामले को फिर खोलने का राजनीतिक संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। यह कदम तब आया है जब ज्ञानेश कुमार को लेकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर विपक्षी दलों का विरोध जारी है और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने एसआईआर से जुड़े फैसलों को आयोग द्वारा सामूहिक रूप से लिया गया बताया है। केरल सरकार का कहना है कि कानूनी राय लेने के बाद जांच में कोई कानूनी बाधा नहीं पाई गई। वहीं, बीजेपी ने दो दशक पुराने मामले को फिर खोलने के समय और पिछली सरकारों में हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल ज्ञानेश कुमार की ओर से नई विजिलेंस जांच पर कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जांच के जरिए अब पुराने आरोपों, परियोजना से जुड़े रिकॉर्ड और पहले की जांच की स्थिति की नए सिरे से पड़ताल की जाएगी।

लोकसभा चुनाव-2029 की बहस के बीच टीवीके इंडिया गठबंधन में शामिल !

विजय की पीएम उम्मीदवारी पर संशय

भाजपा सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राजनीतिक मुकाबला और प्रभावी ढंग से लड़ा जा सकेगा। विजय के इस निर्णय को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें हैं। एक पहलु इसे राजनीतिक मजबूरी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, पिछले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में टीवीके सबसे बड़ा दल बनकर उभरा था, लेकिन उसे केवल 108 सीटें ही मिली थीं। सरकार बनाने के लिए उसे कम से कम 10 और सीटों की आवश्यकता थी। ऐसे में कांग्रेस, टीवीके, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,

आईयूएमएल जैसे दलों के समर्थन से पार्टी राज्य की सत्ता तक पहुंच पाई। वहीं, इस फैसले को रणनीतिक आवश्यकता के रूप में भी देखा जा रहा है। पहली बात तो यह कि जिस गठबंधन के साथ टीवीके राज्य में सरकार चला रहा है, गठबंधन का ढांचा भी काफी हद तक वैसा ही है। दूसरा, यह कदम टीवीके को लोकसभा चुनाव 2029 में सीटों की मजबूत दावेदारी पेश करने का अवसर देगा, जिससे उसे राष्ट्रीय स्तर पर किसी नए गठबंधन की तलाश या गठन से मुक्ति मिलेगी। शनिवार को हुई इस महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस, टीवीके, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी,

बीसीके, एमडीएमके और आईयूएमएल के शीर्ष नेता शामिल हुए। टीवीके का प्रतिनिधित्व अथर्व अर्जुन और मारी विल्सन ने किया। टीवीके पहले मजबूती से सी जोसेफ विजय को प्रधानमंत्री पद के अगले चेहरे के तौर पर पेश कर रही थी, जिसके चलते कांग्रेस के साथ उसकी तीखी बयानबाजी भी हुई थी। अर्जुन ने कहा था, मैं आज साफ तौर पर कहता हूं कि प्रधानमंत्री दक्षिण से ही आना चाहिए और दक्षिण से ही प्रधानमंत्री बनेगा, हो सकता है अभी नहीं। भविष्य में वह हर भारतीय का प्रतिनिधित्व करेगा और हर भारतीय के साथ समान व्यवहार करेगा। अब गठबंधन में शामिल होने के बाद विजय

बद्रीनाथ धाम में 2023 का टूटा रिकॉर्ड, इस साल अब तक 18.67 लाख श्रद्धालु पहुंचे

चमोली (एजेंसी)। बद्रीनाथ धाम की तीर्थयात्रा ने इस साल एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अब तक 18.67 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या 2023 में बने 18.39 लाख भक्तों के पिछले रिकॉर्ड को पहले ही पार कर चुकी है। बद्रीनाथ धाम आने वाले भक्तों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी के बीच, इस साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही रिकॉर्ड टूट गया। तीर्थयात्रा में लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए उम्मीद है कि इस साल भक्तों की संख्या 20 लाख का आंकड़ा पार कर जाएगी। अधिकारी और प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को 14,000 से ज्यादा भक्त बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री नाथ की पूजा-अर्चना की। तीर्थयात्रा को कड़ी निगरानी और तैयारी के साथ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भक्तों को सुरक्षा को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में आपदा प्रबंधन विभाग को चौबीसों घंटे अलर्ट है। ये जिले चार धाम यात्रा मार्ग से जुड़े अहम जिले हैं। चार धाम यात्रा के दूसरे चरण में मानसून के बाद तीर्थयात्रियों की आवाजाही में फिर से तेजी आई है और बद्रीनाथ धाम की ओर जाने वाले भक्तों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ के कारण बद्रीनाथ नेशनल हाइवे पर कई जगहों पर जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे मंदिर की ओर जाने वाले भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रास्ते में गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण कर्णप्रयाग और बद्रीनाथ के बीच कई जगहों पर लंबी कतारें देखी गईं। अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

मणिशंकर के बयान पर सिब्बल का पलटवार: भारत ही क्यों करे शांति के लिए रियायत?

पूर्व विदेश सचिव ने कांग्रेस नेता को दिखा दिया आईना



पाकिस्तान के साथ बातचीत की मेज पर बैठने का साहस क्यों नहीं दिखाता। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर के बयान पर केवल सिब्बल ने पलटवार कर लिखा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ वर्षों तक बातचीत की है, इतना ही नहीं मुंबई

आतंकी हमले के बाद भी शांति की कोशिश की, लेकिन इसका कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने सार्क की भी प्रभावी रूप से निष्क्रिय कर दिया है। पूर्व विदेश सचिव सिब्बल ने सवाल किया कि

मौजूदा पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनिर के नेतृत्व में पाकिस्तान भारत के साथ शांति के लिए क्या रियायत देने को तैयार है, जबकि मुनिर दो-राष्ट्र सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और हिंदू-मुस्लिम के बीच समानता के विचार को स्वीकार नहीं करते। चीन को लेकर भी सिब्बल ने अत्यर की दलील पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच भी वर्षों से बातचीत जारी है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि चीन सीमा विवाद को समान और न्यायसंगत आधार पर सुलझाने को तैयार है। पूर्व विदेश सचिव सिब्बल ने कहा कि शांति स्थापित करने का पूरा दायित्व भारत पर डालना उचित नहीं है, और यह मानना कि भारत ही समस्या पैदा करने वाला पक्ष है, एक अनावश्यक कूटनीतिक आत्म-भर्त्सना है।

छलका सीएम यादव का दर्द बोले- बहुत महंगी पड़ गई लाडली बहना

भोपाल, एजेंसी।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना को बहुत खचीली बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बनने के समय उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि आर्थिक बोझ इतना भारी होगा। राजधानी भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात हल्के-फुल्के अंदाज में कही, जिस पर राजनीतिक हलकों और सोशल मीडिया पर मिर्ची-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के रवींद्र भवन में बुदेली समागम-2026 कार्यक्रम में छतरपुर की बुदेली कटेट क्रिएटर बिन्नी रानी के सवालों का जवाब दे रहे थे। जब बिन्नी ने बेटियों के लिए सरकार की भावी योजनाओं के बारे में पूछा, तो सीएम यादव ने हंसते हुए कहा, मुझे क्या मालूम था कि मुख्यमंत्री बनते ही इतनी भारी मार पड़ती है, लाडली

बहना योजना बहुत खचीली साबित हुई। उन्होंने मजाकिया लहजे में आगे कहा, बेटा ये अंदर की बात हैज मुझे क्या पता था कि मुख्यमंत्री बनते ही ऐसी मार पड़ती है। मोहन यादव के इस बयान पर विपक्षी दल कांग्रेस ने तुरंत निशाना साधा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता उमंग सिंघर ने तंज कसते हुए कहा, चुनाव से पहले लाडली और सत्ता में आते ही परेशानी। यही है भाजपा का महिला समस्या। कांग्रेस ने भाजपा पर महिलाओं के प्रति दोहरे रवैये का आरोप लगाया, जिसमें चुनावी लाभ के लिए योजनाओं का वादा किया जाता है, लेकिन सत्ता में आने पर उनके वित्तीय बोझ पर चिंता व्यक्त की जाती है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि बहनों के मामले में कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने लाडली बहना योजना के



की प्रधानमंत्री उम्मीदवारी को लेकर नए सिरे से बहस शुरू हो सकती है।हाला ही में ऐसी खबरें भी आई थी कि द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम सांसद कनिमोई कांग्रेस के बिना तीसरे मोर्चे के लिए क्षेत्रीय दलों

को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं। इस संबंध में उन्होंने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी, हालांकि इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी।